

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २५ जुलाई, 2013

विषय— जनपद चमोली में जिला सेवा योजन कार्यालय, चमोली के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 0.022 है० सिविल सोयम भूमि श्रम एवं सेवायोजन विभाग के नाम निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं-101/छब्बीस-32(2011-12) दिनांक 04-10-2012 के रांदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद एवं तहसील चमोली के अन्तर्गत ग्राम गोपेश्वर के नॉन जेड०४० ख०खा०सं०-१८६ के खसरा संख्या-८७ रक्वा ०.०५८ है० मध्ये ०.०२२ है० भूमि, जो श्रेणी-९(3)ड के तहत बंजर दर्ज अभिलेख है, को वित्त अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या-२६०/वित्त अनुभाग-३/२००२ दिनांक १५-२-२००२ में निहित प्राविधानों एवं श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1— भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2— जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या ३ वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

- 7— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8— प्रश्नगत नॉन जैड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9— इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या—1132/2011 (एस०एल०पी०)/(सी) संख्या— 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में मारो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के बिन्दु संख्या—1 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ०प०संख्या—१९० / समदिनांकित/ 2013

- प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1— प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
 - 2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - 4— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 5— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
 - 6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।